IJIRSET
International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 10, Issue 10, October 2021

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.569

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com www.ijirset.com

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 10, Issue 10, October 2021 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1010109|

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में युवा नेतृत्व: सचिन पायलट के व्यक्तित्व के संदर्भ में

Dr. Dhiraj Bakolia

Associate Professor, Dept. of Political Science, Govt. Lohia College, Churu, Rajasthan, India

सार

सचिन पायलट ने कहा कि हमें यंग जनरेशन को केवल नारे लगाने और दरी बिछाने के लिए उपयोग में नहीं लेना है। आज के युवाओं ने लीडरशिप की क्षमता और गुण हैं। हमें उनकी इस क्षमता को उपयोग में लेते हुए युवाओं को नेतृत्व का अवसर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम नई जनरेशन के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। वर्तमान समय में देश और प्रदेश के कई युवा नेता है जिनकी नेतृत्व क्षमता किसी से छिपी नहीं है। सामाजिक समूहों का मत ही जनतंत्र का निर्माण करता है और इनके आधार पर ही राजनीतिक नेतृत्व की दशा-दिशा तय होती है। ऐसे में यदि कोई सामाजिक समूह सत्ता एवं जनतांत्रिक स्रोतों के वितरण में सक्रिय हस्तक्षेप नहीं कर पाता तो पर्याप्त मतशक्ति के बावजूद राजनीतिक नेतृत्व में उसकी सापेक्ष भागीदारी संभव नहीं हो पाती। यहां इससे आशय भारतीय राजनीति में युवाओं और महिलाओं के रूप में दो सामाजिक वर्गों से है। भारत युवा आबादी वाला देश है और बीते कुछ दशकों में यहां 'युवा' मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ी है।

अलग-अलग जाति समूह एवं राजनीतिक दलों में बंटे होने के बावजूद राजनीतिक हस्तक्षेप की अपनी क्षमता के कारण उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों में भागीदारी मिलने लगी है। अब वे केवल अपने-अपने दलों की 'युवा इकाई' की राजनीति तक सीमित नही हैं, बल्कि उन्हें अपने-अपने दलों में शीर्ष पर भी जगह मिल रही है। इसी तरह आधी आबादी यानी महिलाओं में मत देने की चाह तो बढ़ी है, लेकिन अभी उनमें राजनीतिक हस्तक्षेप की अपेक्षित शक्ति विकसित नहीं हो पाई है। शायद यही कारण है कि आबादी के अनुपात में उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

परिचय

पुरुष प्रधान समाज के प्रभाव में होने के कारण महिलाओं की भूमिका अभी भी मां, बहन और पत्नी के रूप में ही बनी हुई है। उनका मत पुरुष मतों का अनुषंगी माना जाता है। हालांकि समय के साथ यह स्थिति थोड़ी बदली है। बदली छवि से महिलाओं का राजनीतिक हस्तक्षेप मुखर हुआ है। वे अपने परिवार की परिपाटी से अलग अपने विवेक से मतदान करने लगी हैं।[1]

क्या दो दशक पहले हम किसी राज्य में युवा मुख्यमंत्री की कल्पना कर सकते थे? अतीत में यह पद अमूमन वरिष्ठ नेताओं को ही मिलता था, किंतु अब त्रिपुरा और महाराष्ट्र में युवा मुख्यमंत्री ही हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में युवा चेहरे इस पद के लिए सशक्त दावेदारी कर रहे हैं। जल्द चुनावों का सामना करने जा रहे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान में सचिन पायलट अपने दल में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में उभर रहे हैं। वहीं बिहार में तेजस्वी यादव आगामी चुनाव में विपक्षी राजनीति का नेतृत्व करेंगे।

सचिन पायलट (जन्म 7 सितम्बर 1977) एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा राजस्थान सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे हैं।[2] वे भारत सरकार की पंद्रहवीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री में मंत्री रहे है। वर्तमान में वे राजस्थान के टोंक विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।[3] ये चौदहवीं लोकसभा में राजस्थान के दौसा लोकसभा क्षेत्र का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं। वे 2014 से 14 जुलाई 2020 तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे । 14 जुलाई को पिछले कुछ दिनों से चल रही राजनीतिक उठापटक के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया। [4] उपमुख्यमंत्री के पद से हटाए गए- 14 july 2020

सचिन पायलट राजस्थान से हैं। उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट थे जो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से थे। पायलट की प्रारंभिक शिक्षा नयी दिल्ली के एयर फोर्स बाल भारती स्कूल में हुई। उन्होंने अपने स्नातक की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हासिल की। इसके बाद पायलट ने अमरीका स्थित पेंसिलवानिया विश्वविद्यालय के व्हॉर्टन स्कूल से एमबीए की डिग्री भी हासिल की। सचिन ने अपनी आरम्भिक शिक्षा दिल्ली की आर्मी स्कूल से पूरी की इसके बाद मैनेजमेंट की पढ़ाई इन्होने अमेरिका के पेन्सिल्वेनिया से की। ये एक राजनेता होने के साथ साथ युवाओं के लिए आदर्श व मोटिवेशनल वक्ता भी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति का नया रूप माना जाता हैं। जो इनके व्यक्तित्व में साफ़ झलकता है। भारत लौटने पर सन २००२ में अपने पिता के

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 10, Issue 10, October 2021 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1010109|

जन्मदिन १० फरवरी को श्री सचिन कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर एक बड़े किसान सभा का आयोजन भी किया गया। १३ मई २००४ को पायलट चौदहवीं लोकसभा के लिए दौसा सीट से चुने गये जिसमें उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को १.२ लाख मतों से हराया। २६ साल की उम्र में वे भारतीय सांसद बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। पायलट केंद्र सरकार के गृह विभाग के स्टैंडिंग कमिटी के सदस्य एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके है। दिसंबर 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनावों के पश्चात वे राजस्थान के 5 वें उप मुख्यमंत्री भी बने।अशोक गहलोत से मतभेदों को लेकर 14 जुलाई 2020 को उन्हें उप मुख्यमंत्री एवम राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। पायलट का विवाह सारा अब्दुल्लाह से सन २००४ में हुआ, जो कश्मीरी नेता फारूक अब्दुल्ला की सुपुत्री हैं।

सचिन पायलट भारत के सबसे कम उम्र के संसद सदस्यों में से एक है। सचिन पायलट को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री चुना गया है। वह स्वर्गीय राजनेता राजेश पायलट के पुत्र हैं। पायलट ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक डिग्री प्राप्त की है। अपनी स्नातक पूरी करने के दिल्ली ब्यूरो ऑफ़ ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कॉर्पोरेशन और उसके बाद अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जनरल मोटर्स में दो साल काम किया। व्हार्टन बिजनेस स्कूल (पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, यू.एस.ए.) में बहुराष्ट्रीय प्रबंधन और वित्त में विशेषज्ञता के साथ अपनी एमबीए डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीति में शामिल होने का फैसला किया। 26 साल की उम्र में, वह 14 वीं लोक सभा के लिए राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सबसे कम उम्र के सांसद के रूप में चुने गए। 2009 में, वह अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर से चुने गए और यूपीए सरकार में राज्य मंत्री बने। उन्होंने केंद्र सरकार में विभिन्न समितियों को अपनी सेवाएं दीं। वह वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और 2018 विधानसभा चुनावों में पार्टी की चुनाव गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे हैं। पायलट ने 2004 में सारा अब्दुल्ला से विवाह किया था। सारा जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं।[2]

सचिन पायलट को उड़ान भरने का शौक है और वह एक अच्छे शूटर भी है। उन्हें 1995 में एनवाई, यूएसए से अपना निजी पायलट लाइसेंस (पीपीएल) भी प्राप्त किया है। शूटिंग में, उन्होंने कई राष्ट्रीय राइफल और पिस्तौल शूटिंग चैम्पियनशिप में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें क्षेत्रीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में भी सेवाएं दी हैं। इसलिए उन्हें क्षेत्रीय सेना में लेफ्टिनेंट पायलट के रूप में भी जाना जाता है। किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सचिन रुचि लेते हैं। उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और वर्तमान मामलों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थशास्त्र, कृषि और ग्रामीण विकास, रणनीतिक और विदेशी संबंधी मामलों में विशेष रूचि है। उन्होंने 2001 में अपने पिता पर एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का शीर्षक "राजेश पायलट: इन स्पिरिट फॉरएवर" है।

विचार-विमर्श

भारत युवाओं का देश बना हुआ है, लेकिन देश में नई चेतना का संचार करने वाली युवा राजनीतिक पीढ़ी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद, बसपा जैसे दलों में बड़ी उम्र के नेता अगुआ बने हुए हैं। कांग्रेस में 47 साल के राहुल गांधी हैं पर उनमें नेतृत्व की क्षमता का साफ अभाव उजागर हो चुका है। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा में कोई लोकप्रिय युवा नेता दिखाई नहीं देता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या युवा भारत का नेतृत्व हमेशा बुजुर्ग नेताओं के हाथ में ही रहेगा? आज विश्व में भारत सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। भारत के मुकाबले चीन, अमेरिका बूढ़ों के देश हैं। चीन में केवल 20.69 करोड़ और अमेरिका में 6.5 करोड़ युवा हैं। हमारे यहां 125 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या में 65 प्रतिशत युवा हैं। इनकी उम्र 19 से 35 वर्ष के बीच है, लेकिन देश के नेतृत्व की बागडोर 60 साल से ऊपर के नेताओं के हाथों में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में तीन-चौथाई नेता सीनियर सिटीजन की श्रेणी वाले हैं। राजनीतिक संगठनों में भी युवाओं से अधिक बूढ़े नेता पदों पर आसीन हैं। मौजूदा संसद में 554 सांसदों में 42 साल से कम उम्र के केवल 79 सांसद हैं। इनकी आवाज संसद में न के बराबर सुनाई पड़ती है। युवाओं की अगुआई कहीं नजर नहीं आती। उनकी ओर से कहीं कोई सामाजिक, राजनीतिक बदलाव या किसी क्रांति की हुंकार भी सुनाई नहीं पड़ रही है। अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल उभर कर आए। देश को उनकी सोच परिवर्तनकारी लगी। उन्हें अवतारी पुरुष बताया जाने लगा पर 2-3 साल गुजरते-गुजरते वे असफल साबित होने लगे। वे मैदान में विरोधियों को झेल नहीं पाए। उन्हें विपक्ष ने असफल साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विरोधी उन पर भारी साबित हुए और वे उनके हाथों शिकस्त खा गए दिखते हैं। राहुल गांधी कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। अपने कामों से उनकी हंसी ज्यादा उड़ रही है। 47 साल के ज्योतिरादित्य सिंधिया, 40 वर्षीय सचिन पायलट अपने परिवारों की राजनीतिक विरासतों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। वे भी लकीर के फकीर बने नजर आते हैं। इन्होंने राजनीति में आकर कोई नई सोच या दिशा नहीं दी। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव कोई चमत्कार नहीं कर पाए। हालांकि पिछली बार उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें युवा जान कर सत्ता सौंपी थी पर वे पारिवारिक झगड़े में ही उलझ कर रह गए। इस बार प्रदेश की उसी युवा पीढ़ी ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। आज की राजनीति में राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट से लेकर अखिलेश यादव तक कई युवा हार्वर्ड जैसे विदेशी विश्वविद्यालयों से पढ़ कर आए हुए हैं। गांधी, नेहरू, पटेल भी युवावस्था में विदेश से पढ़कर देश का राजनीतिक नेतृत्व किया था। उन नेताओं ने देश को धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान कराने में अपना योगदान दिया। राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में श्यामाचरण शुक्ला और विद्याचरण शुक्ला के परिवार से युवाओं में उभर

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 10, Issue 10, October 2021 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1010109|

कर कोई नहीं आ पाया।[3] पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बाद कोई नहीं दिख रहा। ओडिशा में नवीन पटनायक भी किसी युवा को आगे नहीं ला पाए। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव का परिवार धर्म की लौ जगाने में ज्यादा भरोसा रखता है। दक्षिण भारत में रजनीकांत और अब कमल हासन दोनों ही 60 से ऊपर की अवस्था में आ कर राजनीति में उतरने की सोच रहे हैं और अभी भी वहां 85 साल से अधिक उम्र के हो चुके करुणानिधि का दबदबा है और एसएम कृष्णा जैसे नेता कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में आ रहे हैं। अन्ना आंदोलन के बाद लगता है कि देश के युवा का बदलाव की राजनीति और वैचारिक क्रांति में भरोसा कम होता जा रहा है। वह यथास्थितिवादी होता जा रहा है। वह परंपरा को तोडने के बजाय परंपरापूजक होता जा रहा है। आमतौर पर माना जाता है कि युवा का मतलब है परंपराओं को चुनौती देने वाला और बदलाव में विश्वास रखने वाला। समाज का यह तबका किसी देश में बदलाव का अगुआ होता है। हाल के समय में लगता है युवा खासतौर से मध्यवर्गीय युवा धारा के विरुद्ध नहीं, धारा के साथ बहने लगा है। बदलाव के बजाय परंपराओं में, यथास्थिति में भविष्य देख रहा है। युवा सामाजिक, राजनीतिक जकड़बंदी से टकराने के बजाय उससे समझौता करने के मूड में दिखाई देने लगा है। यह बात भी सही है कि सत्ता की ओर से युवाओं को बदलाव की चेतना, आंदोलन से दूर रखने और इन आंदोलनों को कमजोर करने की योजनाबद्ध कोशिशें हुईं और उसे काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। असल में मौजूदा व्यवस्था युवाओं की बेचैनी, उसके जोश, उसकी क्रिएटिविटी को कुचलने का काम कर रही है। इस कारण युवा राजनीति के अलावा अन्य क्षेत्र में जा रहे हैं। लकीर के फकीर बन बैठे हैं युवा नेता भारत में पिछले कुछ सालों में कई युवा नेता राजनीतिक पटल पर उभरते दिखे। लेकिन वे जितनी तेजी से उभरे उतनी ही तेजी से गायब भी हो गए। दरअसल, पार्टी कोई भी हो उसे युवा नेतृत्व पसंद नहीं हैं और जो युवा नेता हैं वे लकीर के फकीर बन बैठे हैं। आलम यह है कि भारतीय राजनीति में उम्रदराज नेता अपने अंतिम समय तक सक्रिय रहने के आदि हो गए हैं। इस कारण युवा अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। देश के आम युवाओं की बात करें तो उन का हाल यह है कि वे भेड़ों की तरह हांके जा रहे हैं। चारों ओर युवाओं की केवल भीड़ है। हताश, निराश और उदास युवा। एसोचैम के अनुसार, आज 78 करोड़ युवा सोशल मीडिया पर तो सक्रिय हैं पर उन में राजनीतिक व सामाजिक रचनात्मकता नदारद है। शोपीस बनकर रह जाते हैं युवा नेता राजनीति में युवाओं को आगे लाने की बात होती है, युवा नेतृत्व की बात चलती है पर पार्टी या सरकार का नेतृत्व किसी बड़ी उम्र के नेता को ही सौंपा जाता है। 2008 में राहुल गांधी ने युवा शक्ति से जनाधार बढ़ाने के लिए देशभर से युवाओं के इंटरव्यू किए थे। उसमें 40 युवाओं का चयन किया गया। पर वे आज कहां हैं, उनकी हट कर कोई अलग पहचान नहीं दिखती। पिछले लोकसभा चुनावों में युवाओं का चुना जाना अच्छा संकेत था पर ये युवा ज्यादातर अपनी खानदानी विरासत संभालने आए। कुछ बंधनों को छोड़ दें तो इन युवाओं में जोश और जज्बा तो नजर आता है पर नई सोच नहीं। विचारों में क्रांति लाने का काम नहीं हो रहा है। संसद में सचिन तेंदुलकर जैसे युवा केवल शोपीस बने हुए हैं। वे न खेलों को भ्रष्टाचार, बेईमानी से मुक्त करने के लिए कोई बात करते हैं, न किसी अन्य सुधार की।[4] दलगत राजनीति हो या छात्र राजनीति, दोनों की दशा डांवाडोल है। राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने छात्र राजनीति में भी अपनी घुसपैठ बना रखी है। जेल भेज दिया जाता है युवाओं को पिछले दिनों कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, चंद्रशेखर जैसे युवा नेता उभर कर सामने आए। कन्हैया कुमार ने विश्वविद्यालयों और समाज में व्याप्त धार्मिक, जातीय भेदभाव के लिए आंदोलन छेड़ा। केंद्र सरकार ने देशद्रोह का आरोप लगा कर जेल भेज दिया। गुजरात हार्दिक पटेल ने आक्षरण में भेदभाव को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा किया। उन पर भी मुकदमा कायम किया गया और राजस्थान में कई महीनों तक नजरबंद रखा गया। गुजरात में ही पिछले साल मरी हुई गाय की खाल उतारने पर 4 दलित युवकों की हिंदू संगठनों के लोगों द्वारा की गई बुरी तरह पिटाई के बाद जिग्नेश मेवानी उभर कर सामने आए। इस घटना के विरोधस्वरूप जिग्नेश ने राज्यभर में आंदोलन की अगुआई की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के शब्बीरपुर में दलितों और राजपूतों के बीच हुई हिंसा के मामले में भीम आर्मी के नेता के रूप में चंद्रशेखर उभर कर सामने आए। 35 वर्षीय चंद्रशेखर ने जातीय भेदभाव और हिंसा के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। दिल्ली के जंतरमंतर पर धरना देने के लिए बुलाई गई भीड़ का नेतृत्व किया और बाद में उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।

परिणाम

राजस्थान में पायलट बनाम गहलोत ड्रामे ने कुछ ऐसी परतें उघाड़ दी हैं जिन्हें लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमेशा छिपाने का आरोप लगाया है, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री चुनने के मामले में. भाजपा कांग्रेस पर 'दरबारी' होने और युवा नेताओं को बर्खास्त या दरकिनार करने के लिए पुराने घाघ नेताओं का पक्ष लेने का आरोप लगाती है. यहां तक कहा जाता है कि कांग्रेस युवा नेताओं को बढ़ावा नहीं देती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई भी राहुल गांधी के रास्ते में आड़े आए.

लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, अदिति सिंह और अब सचिन पायलट से जुड़ी हालिया घटनाएं यह स्पष्ट करती हैं कि यह कांग्रेस की अधीर युवा पीढ़ी है जो पार्टी की रैंक व्यवस्था तोड़ने के लिए खुलकर सामने आ रही है. उनके ऐसा करने की वजहें अलग-अलग हो सकती हैं- लालच, सत्ता की आकांक्षा, निराशा, छिछली विचारधारा, आत्म-सुरक्षा की भावना या फिर एक पुरानी पार्टी के अंदर संगठनात्मक ढांचे से जुड़े असल मुद्दे. लेकिन अपनी बदली सोच के खुले प्रदर्शन में वह लगभग

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 10, Issue 10, October 2021 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1010109|

एक ही लय में दिखते हैं. कांग्रेस के पुराने नेता इस पर जोर देते हैं कि जैसा अशोक गहलोत ने हाल में एक साक्षात्कार में कहा, पार्टी के युवा नेताओं में धैर्य की कमी है. गहलोत ने तर्क दिया कि उन्होंने 1984 में कांग्रेस की राजस्थान इकाई की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए 14 साल तक इंतजार किया और सचिन पायलट को भी इसी तरह धैर्य दिखाना चाहिए था क्योंकि राजनीति इसी तरह चलती है. कांग्रेस ने सचिन पायलट के सिर्फ यह कहने भर पर उनसे सभी पद छीन लिए कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वह पार्टी छोड़ देंगे. टेप लीक हो रहे हैं और एक-दूसरे पर कीचड़ उछालना जारी है. गहलोत खेमा और कांग्रेस की पूरी आईटी सेल यह साबित करने में जुटी है कि पायलट एक 'मौकापरस्त' हैं जिनकी अपनी विचारधारा कभी ठीक नहीं रही.

लेकिन कांग्रेस को 1970 के दशक की भारतीय राजनीति से इतर देखने की जरूरत है. हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं और खेल एकदम बदल गया है. मोदी और शाह के जमाने में हार-जीत नितांत निजी है. भाजपा की सत्ता की लालसा, किसी भी तरह जीत हासिल करना, खतरनाक है लेकिन प्रेरणादायी भी है. यही वजह है कि इसके आलोचक भी राजस्थान संकट के मामले में खुद को बेवकूफ बनाने के लिए कांग्रेस की आलोचना करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते.[5]

पायलट के जाने से कांग्रेस में प्रतिभा की कमी और गहरा जाएगी. कई लोग सोचते हैं कि कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी बात यही हो सकती है कि छिछली विचारधारा वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए. लेकिन यह तो समय ही बताएगा कि करिश्मा विकसित नहीं किया जा सकता, कुछ लोग इसके साथ ही पैदा होते हैं. कांग्रेस अंततः यह तभी समझ पाएगी जब उसे अहसास होगा कि उसके पास नई पीढ़ी के ऐसे नेताओं की कमी है जिनके साथ भारत के लोग खुद को जोड़ सकें.

निष्कर्ष

राजस्थान सियासी हलचल (Rajasthan Political Crisis): पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक आदत बना ली है कि बिना कोई संकट के बादल के ही सियासी उलझनों की बारिश कैसे किया जाए। एक विलक्षण सी आदत बनती जा रही है कांग्रेस और उसे नेताओं में कई अपने ही पाले में गोल कैसे किया जाए।

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मीडिया (Main stream & Social Media दोनों) से लेकर जमीन पर भी आम जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा था। बीते एक दशक में BJP और उसके प्रवक्ता शायद पहली दफा इस तरह से बैकफुट पर खेल रहे थे। लेकिन तभी अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा और फिर संभावित भावी अध्यक्ष का सत्ता-मोह इस पूरे किए धरे पर एक सवालिया निशान फैला दिया है।

ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई ऐसी "सेल्फ गोल" वाली स्थिति में पार्टी किसी एक नेता के महत्वाकांक्षाओं के कारण आ खड़ी हुई है। और ऐसा आखिरी बार हुआ है, इसकी की संभावना कम ही लगती है। क्योंकि समस्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में है जो किसी बड़े नेता के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और पार्टी के सामूहिक लक्ष्य के बीच संतुलन बना पाने में असक्षम मालूम पड़ती है।

इस से पहले ताजातरीन पंजाब, उसके पहले मध्यप्रदेश, गोआ, मेघालय, अरुणाचल आदि ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पार्टी ऐसी ही राजनीतिक भँवर में उलझी और बिखरकर रह गयी। इन सब जगह एक ही ढर्रे की राजनीति समझ मे आती है कि शीर्ष नेतृत्व किसी व्यक्ति विशेष को विश्वास में लिए बगैर कोई बड़े कदम जैसे मुख्यमंत्री को बदलना या पार्टी संगठन में फेर बदल की कोशिश करती है।

राजस्थान से पहले भी कई अन्य उदाहरण हैं जहाँ पार्टी नेतृत्व या उनके वफादारों ने पार्टी को संकट में डाला है। गोआ के 2017 विधानसभा चुनाव-नतीजों के बाद सबसे बड़ी पार्टी (17 सीट) के तौर पर उभरी कांग्रेस सरकार नही बना पाई और दूसरे नंबर की पार्टी BJP ने सरकार बना ली।

बाद में पूर्व मुख्यमंत्री ल्युजिन्हों फलेइरो (Luzinho Faleiro) ने दावा किया कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक अनुभवी दिग्विजय सिंह ने उन्हें सरकार बनाने के दाव को राज्यपाल के समक्ष पेश करने से रोक दिया था। परिणामस्वरूप कांग्रेस मे टूट और बिखराव सामने आया जो आजतक गोआ में जारी है।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 10, Issue 10, October 2021 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1010109|

अरूणाचल प्रदेश में भी 2015-16 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नबम तुकी और उनके भतीजे नबम राबिया के बीच के गतिरोध के दौरान भी कांग्रेस आलाकमान या हाई-कमान पार्टी के प्रदेश इकाई के भीतर के मूड को भांपने में नाकाम रही थी। पार्टी ने तुकी के जगह कलिखो पुल को मुख्यमंत्री बना दिया लेकिन हलचल नहीं रुक पाया और अंततः पार्टी में यहाँ भी टूट हुई।

मेघालय में भी पिछले साल 17 में से 12 विधायकों ने मुकुल संगमा के नेतृत्व में पाला बदल लिया और कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए।[5]

मध्यप्रदेश में भी एक तरफ़ ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरी तरफ कमलनाथ-दिग्विजय सिंह की जोड़ी के बीच के तनाव को खत्म करने में पार्टी आलाकमान नाकाम रही जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को राहुल गांधी के करीबी बताया जाता था।

किसी निर्णायक संतुलन न बन पाने के कारण सिन्धिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ BJP में शामिल हो गए और कांगेस BJP पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाते रह गई लेकिन मध्य प्रदेश की सत्ता अपने हाँथ से गंवा दी।

राजस्थान से पहले लगभग यही खेल पंजाब में भी हुआ था जहाँ एक पुराने क्षत्रप तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री तथा नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ अमरिंदर सिंह को अपने विधायकों का वह समर्थन नहीं प्राप्त था जो आज राजस्थान में अशोक गहलोत को हासिल है।

पंजाब की राजनीति को उस समय देखकर ज्यादातर राजनीतिक पंडित अंदाजा लगा रहे थे कि कांग्रेस की वापसी होगी। क्योंकि BJP और अकाली दल का गठबंधन टूट गया था, आम आदमी पार्टी अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही थी।

लेकिन अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद सिद्धू को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और फिर चन्नी को CM बनाने की कोशिश इस कदर नाकामयाब हुई कि सुफड़ा साफ होने जैसी पराजय हाँथ लगा। चन्नी आज कहाँ है, किसी को कुछ मालूम नहीं; सिद्दू भी सक्रिय राजनीति में नही दिखाई दे रहे हैं; अमरिंदर सिंह ने हाल में BJP की सदस्यता ले ली और कांग्रेस अब अपनी जमीन वहाँ खो चुकी है।

राजस्थान में भी लगभग वैसी ही कोशिश हो रही है। सचिन पायलट (Sachin Pilot) निःसंदेह बहुत सक्रिय, युवा और पसंदीदा चेहरा होंगे लेकिन क्या शीर्ष नेतृत्व ने अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राजी करते वक़्त यह सब बताया था? क्या उन्हें विश्वास में लिया गया था कि उनके उत्तराधिकारी सचिन पायलट होंगे जिन्हें नेतृत्व CM बनाना चाहती है? क्या विधायकों से किसी ने इसमुद्दे पर राय मशविरा की थी?

अगर इन सवालों के जवाब हाँ है, तो फिर अशोक गहलोत जैसे लोग को पार्टी में रहने लायक नहीं है। और अगर इनके जवाब ना है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को अभी फिलहाल बैठकर आत्ममंथन की आवश्यकता है, पदयात्रा और जन समर्थन की नहीं।

पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा समय रहते बीच-बचाव न करने का यह सिलसिला एक राज्य के बाद दूसरे और फिर तीसरे राज्य में लागतार जारी है। राजनीति के गलियारों में यह शाश्वत सच है कि कांग्रेस जैसी पुरानी और बड़ी पार्टी में लोगों के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होंगे ही लेकिन यहीं पर पार्टी के आलाकमान और शीर्ष नेतृत्व की भूमिका बनती है कि पार्टी के सामूहिक और पार्टी कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बीच कैसे संतुलन तलाशा जाए।[4,5]

संदर्भ

1. "सचिन पायलट को राजस्थान के उपमुख्यमंत्री पद से हटाया गया". अभिगमन तिथि 14 जुलाई 2020.
2. ↑ "सचिन पायलट को राजस्थान के उपमुख्यमंत्री पद से हटाया गया". अभिगमन तिथि 14 जुलाई 2020.
3. ↑ "बीजेपी के यूनुस खान को हराकर सचिन पायलट बने टोंक विधायक". मूल से 12 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 जुलाई 2020.
4. ↑ "सचिन पायलट को रराजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाया गया". अभिगमन तिथि 14 जुलाई 2020.
5. ↑ Farooq Abdullah unhappy with daughter's wedding to Pilot's son Archived 2008-05-12 at the Wayback Machine रीडिफ डॉट कॉम - १५ जनवरी २००४

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor

Impact Factor: 7.569

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com

Scan to save the contact details